संक्षिप्त समाचार

किन्नौर में बड़ा हादसा, खराब मौसम के कारण हिमस्खलन; तीन मजदूरों की मौत

किन्नौर, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। प्रदेश के किन्नौर जिले के मुसरिंग में सोमवार को हिमस्खलन में झारखंड के तीन मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य मजदूर घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भाभा घाटी इलाके में बर्फीला तूफान आने के बाद हिमस्खलन हुआ। उन्होंने बताया कि हिमस्खलन के समय बड़ी संख्या में मजदूर कार्यस्थल पर दोपहर का भोजन कर रहे थे। भाभा घाटी के तहसीलदार अरुण कुमार ने घटना की पुष्टि की है। इस घटना में तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि झारखंड के रहने वाले सीमन किंडो और बिरया की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि झारखंड के ही रतन लाल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल के रहने वाले एक मजदूर कृष्णा को गंभीर चोटें आई और उसे रामपुर अस्पताल स्थानांतरित किया गया जबकि चंद्र नाथ को कटगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तूफान आने के बाद इलाके में हिमस्खलन हुआ था जिसमें तीनों मजदूर दब गए थे। अब तक तीन लोगों की मौत का मामला सामने आया है। भावानगर थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर के अगुवाई में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की एक टीम हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। मौसम विभाग ने 13 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए बताया कि 13 और 14 मार्च को चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, किन्नौर और शिमला के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और तूफान के साथ बारिश की भी संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

महाराष्ट्र में 31 पर भाजपा एवं 13 सीटें शिवसेना लड़ सकती है चुनाव?

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार कैंप) के बीच सीट शेयरिंग पर मुहर लगने की खबरें हैं। हालांकि, अब तक किसी ने भी आधिकारिक तौर पर आंकड़ों का खुलासा नहीं किया, लेकिन अटकलें हैं कि तीनों दल राज्य 48 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने के लिए तैयार हैं। भाजपा मंगलवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। एक रिपोर्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा 31, शिवसेना 13 और एनसीपी 4 सीटों पर लड़ेगी। सूत्रों ने कहा, महायुति गठबंधन समझौते पर पहुंच गया है, जहां भाजपा 31 सीटों, शिवसेना 13 और अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ेगी। पवार को बारामती, शिरूर और रायगढ़ के साथ-साथ परभणी भी दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शिवसेना 13 सीटों पर मैदान में उतरेगी, जिसके बदले में भाजपा को मुंबई की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। खबर है कि शिंदे सेना ने उत्तर-पश्चिम मुंबई सीट के स्थान पर ठाणे सीट चुनी है। इसे सीएम शिंदे का गढ़ भी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक, डील के तहत शिंदे सेना दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से मैदान में उतरेगी। फिलहाल, यहां से राहुल शेवाले सांसद हैं। खबरें हैं कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) ने यहां अनिल देसाई को उम्मीदवार बनाने की तैयारी की है। उन्होंने अब तक आधिकारी तौर पर कुछ नहीं कहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चर्चा के दौरान सीएम शिंदे को मनाने में सफल रहे।

खाटू श्याम मेला में नियम बदले, भक्त इस बार आठ फीट से अधिक ऊंचा निशान नहीं लगा सकेंगे

सीकर, एजेंसी। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला 11 मार्च से शुरू हो गया है। मुख्य मेला एकादशी पर 21 मार्च को भरेगा। मंदिर कमेटी का अनुमान है कि 11 दिन चलने वाले मेले में 25 लाख भक्त आएंगे। सीकर जिला प्रशासन ने कई चीजों पर रोक लगाई गई है। बाबा खाटूश्याम के भक्त इस बार आठ फीट से अधिक ऊंचा निशान नहीं लगा सकेंगे। कांच की शीशी और डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को जूते-चप्पल गाड़ी में ही खोलकर आना पड़ेगा। भक्तों को किराए में 50प्रतिशत की छूट रहेगी। मेले में पार्किंग नि:शुल्क रहेगी और नो व्हीकल जोन में किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा पाएंगे। मेले में डेढ़ सौ रोडवेज बसें लगी रहेंगी। वहीं प्राइवेट बसों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है।

क्या केरल और बंगाल रोक सकते हैं सीएए, केंद्र के कानून के खिलाफ राज्य क्या कदम उठा सकते हैं?

नईदिल्ली, एजेंसी। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को देशभर में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। एक ओर जहां केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लंबे समय से इसका विरोध करती रही हैं। सवाल है कि क्या केंद्र के कानून के खिलाफ राज्य क्या कदम उठा सकते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान मामलों के विशेषज्ञ संजय पारीख ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) केंद्रीय कानून है। ऐसे में राज्य कानूनी तौर पर इसे लागू करने से मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन, यदि राज्य को लगता है कि यह कानून संविधान की मूल भावना और संघवाद के खिलाफ है, तो उसे (राज्य) इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है।

पारीख ने बताया कि राज्य कानून का विरोध करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के साथ-साथ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि केरल सरकार विधानसभा में इस कानून के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इसके अलावा, केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है।

क्या बोले राज्य : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित करके अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे ने नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है, इसे मानवता के प्रतीक से धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव के उपकरण में बदल दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएएअधिनियम के नियमों को अधिसूचित करना राजनीति से प्रेरित है, जो आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम चुनाव में अधिक सीट जीतने और सत्ता में आने को लेकर भाजपा के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा, आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के नियम गजट में प्रकाशित हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसका पूरा विवरण देखे बिना इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमने 2019 में देखा कि कई लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार इस फैसले पर पहुंची है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए और इस पर गौर किया जाना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने सीएए को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून करार देते हुए सोमवार को कहा कि इसे दक्षिणी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। विजयन ने यहां एक बयान में कहा, सरकार ने बार-बार कहा है कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। यह रुख बरकरार है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर सीएए लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है, तो वह इसका विरोध करेंगी। सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील करार देते हुए बनर्जी ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती हैं।

राज्य सचिवालय में जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा, ऐसी खबरें हैं कि सीएए को अधिसूचित किया जाएगा। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, उन्हें (केंद्र) नियम सामने आने दीजिए, फिर हम नियमों को पढ़ने के बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे।

केरल में तेजी से फैल रही गलसुआ की बीमारी, एक दिन में आए 190 मरीज

तिरुअनंतपुरम, एजेंसी। केरल में मम्प्स तेजी से फैल रहा है। इसे हिंदी में कंठमाला या गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में एक दिन में ही 190 मामले सामने आए। वहीं मार्च के महीने में अब तक 2505 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दो महीने के भीतर ही 11467 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भी अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि मम्प्स एक वायरस पैरामिक्सोवायरस की वजह से फैलता है। यह संपर्क में आने से या फिर हवा में वॉटर ड्रॉप्लेट्स के माध्यम से ट्रांसफर हो सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी पैदा कर सकता है। प्रभावित होने के तीन से चार घंटे के बाद इसके लक्षण नजर आने लगते हैं। कई बार इसके लक्षण दो से तीन सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वायरस से संक्रमित होने के बाद भी लक्षण ना दिखाई दें। इसमें बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द, सलावरी ग्लैंड में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 70 फीसदी केसों में गालों में सूजन आ जाती है। इस बीमारी को चिपमंक चीक्स के नाम से भी जाना जाता है।

दिमाग को भी कर सकता है प्रभावित : इस बीमारी के असर वैसे तो गंभीर नहीं होते लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह दिमाग, पेन्क्रीज और टेस्टिकल्स को भी प्रभावित कर सकता है। इससे दिमाग में सूजन आने का खतरा बना रहता है। यह ज्यादातर किशोरों को प्रभावित करता है। केरल के मलाप्पुम में मम्प्स के ज्यादातर केस रिपोर्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बच्चों को मम्प्स की वैक्सीन प्राइवेट सेंटर पर लगवाई जा सकती है।

गाजीपुर बस हादसे पर ऊर्जा मंत्री ने 3 अधिकारियों को निलंबित किया, एक की सेवा खत्म कर दी

गाजीपुर, एजेंसी। यूपी के गाजीपुर जिले में सोमवार को एक बस के हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। आग से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। घटना की जानकारी होने पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने तीन अधिकारियों को निलंबित और एक की सेवा समाप्त कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप कुमार राय को निलंबित और लाइनमैन नरेंद्र (संविदा कर्मी) की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता से बात की। सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाते हुए घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सहित प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। साथ ही मंत्री शर्मा पीड़ित परिवारों से स्वयं मिलने के लिए गाजीपुर और मऊ भी पहुंचे।ज्ञात हो कि गाजीपुर के मरदह थाना के 400 मीटर के पास एचटी तार के संपर्क में आने से बस में आ आग लग गई। इस हादसे में कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

फिर थम सकती है दिल्ली, अब एसकेएम ने 14 मार्च को रामलीला मैदान में बुलाई महापंचायत

नईदिल्ली, एजेंसी। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर दिल्ली को थामने की तैयारी कर रही है। एसकेएम ने 14 मार्च (गुरुवार) को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत बुलाई है। इसमें देशभर के किसान, खासकर उत्तर भारत के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे। हालांकि, अभी तक किसान संगठन को दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम से महापंचायत करने की हरी झंडी नहीं मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा के चार सदस्यों की समिति अभी भी दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों से महापंचायत करने की इजाजत लेने की कोशिशों में जुटी है।

खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के डीसीपी हर्षवर्द्धन और एसकेएम नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य मिंदर सिंह पटियाला ने बताया कि 8 मार्च को दिल्ली पुलिस उप आयुक्त के साथ बैठक हुई

थी, जिसमें उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा, हम दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों से भी मिले, जिन्होंने हमें बताया कि अगर दिल्ली पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे देती है तो एमसीडी भी महापंचायत के लिए आसानी से एनओसी दे देगी। एसकेएम किसानों का वही संगठन है, जिसने वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। एसकेएम ने पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। बैठक के बाद दूसरे एसकेएम नेता दर्शन पाल ने कहा कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में महापंचायत में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि महापंचायत शांतिपूर्ण होगी। पाल ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बजाय बसों और ट्रेनों से दिल्ली जाएंगे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, चुनाव होने वाले हों या न होने वाले हों, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमारी मांगें पूरी होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों पर चुनावी घोषणापत्र में अपनी मांगों को शामिल करने के लिए दबाव बनाना है।

बेटा कर्नाटक में मंत्री, अब दामाद को भेजना चाहते हैं लोकसभा, मल्लिकार्जुन खरगे ही तोड़ेंगे नियम!

बेंगलुरु, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष और आईएनडीआईए अलायंस के चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खरगे के लोकसभा चुनाव लड़ने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, खरगे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर खरगे ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हालिया दिनों में ऐसा पहली बार होगा, जब कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से इनकार किया हो। अगर ऐसा होता है तो यह पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खरगे की सीट गुलबर्गा से उनके दामाद राधाकृष्णन दोड्डामणि को उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो खरगे पार्टी के उस नियम को खुद ही तोड़ेंगे, जिसमें कहा गया था कि एक परिवार के एक ही सदस्य को सांसद या विधायक का टिकट दिया जाएगा। हालांकि, इसकी काट में दामाद को दूसरे परिवार का सदस्य बताया जा सकता है। खरगे के बेटे प्रियांग खरगे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रियांक लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हैं। 2022 में

उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में पार्टी ने इस नियम को अपनाने पर खूब चिंतन-मंथन किया था। मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक की गुलबर्गा संसदीय सीट से दो बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में वह ये सीट हार गए थे। उसके बाद वह राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे। फिलहाल खरगे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं और उनका कार्यकाल अभी चार साल बचा हुआ है। 81 वर्षीय खरगे दलित समुदाय से आते हैं। वह लोकसभा में भी नेता विपक्ष रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में वह रेल मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले हफ्ते तक गुलबर्गा सीट पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा में खरगे का नाम शामिल था लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि खरगे इसलिए चुनाव लड़ने से खुद को किनारे कर रहे हैं क्योंकि वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहते हैं बल्कि पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और देशभर में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी रैलियों को संबोधित करना चाहते हैं।

कांग्रेस के कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे कई दिग्गज नेता चुनाव में उतरने को तैयार नहीं

नईदिल्ली, एजेंसी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। इसमें राहुल गांधी के वायनाड सीट और शशि थरूर के तिरुअनंतपुरम से लड़ने का ऐलान हुआ है। अब तक राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने पर तस्वीर साफ नहीं है। यही नहीं उनके अलावा कई ऐसे नेता हैं, जिनके नामों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। यही नहीं चर्चा है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे कई बड़े नेता चुनाव में उतरना ही नहीं चाहते। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव जालोर सीट से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि परिवार की सीट जोधपुर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी जगह पर बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनाव से बेरुखी का नतीजों पर भी असर दिखेगा। असल में यदि ये नेता चुनाव में उतरते तो एक माहौल बनता। खासतौर पर कठिन सीटों पर बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से पार्टी को माहौल बनाने में मदद मिलती। लेकिन नेताओं के डिफेंसिव रुख अपनाने से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इसम मीटिंग में असम, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीटों पर बात हुई है।

राजस्थान, एमपी, गुजरात के अलावा उत्तराखंड में भी सीनियर नेता चुनाव में उतरने के इच्छुक नहीं हैं। हरीश रावत को पार्टी ने हरिद्वार से ऑफर दिया है, जबकि नेता विपक्ष यशपाल आर्य को कुमाऊं की दो सीटें ऑफर की गई हैं। लेकिन दोनों ही नेता चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखते। हरीश रावत तो चाहते हैं कि उनकी जगह पर बेटे को टिकट दे दिया जाए। इसकी वजह यह है कि वह अब राजनीति से संन्यास के मूड में हैं और अपने बदले में बेटे को सेट कराना चाहते है। टिहरी सीट से सीनियर नेता और विधायक प्रीतम सिंह को ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। वरिष्ठ नेताओं के इस रुख से कांग्रेस में अंदरुनी कलह की भी स्थिति है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी ह्यईकमान से कहा है कि सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव में उतरना चाहिए।

लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में 28 अधिकारियों तबादला, सरकार ने 91 पुलिस कर्मियों को भेजा एनआईए

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की है। प्रदेश में पुलिस विभाग में पदस्थ एसपी, सीएसपी, डीएसपी और एसडीओपी का तबादला किया गया है। जिसमें 3 आईपीएस समेत 25 छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल है।

इन्हें किया इधर से उधर : छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा में पदस्थ जिन अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है उनमें डीएसपी सपन चौधरी को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से डीएसपी ऑपरेशन डीआरजी सुकमा, डीएसपी उदयन बेहार को पुलिस मुख्यालय बिलासपुर से हटाकर डीएसपी नक्सल अभियान कोंटा जिला सुकमा, कृष्ण कुमार पटेल को बिलासपुर से हटाकर डीएसपी ऑपरेशन जिला दंतेवाड़ा, डीएसपी कृष्णकांत वाजपेई को कुरुद जिला धमतरी से डीएसपी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा, डीएसपी राजीव कुमार शर्मा को दुर्ग से डीएसपी कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक कांकेर रेंज, डीएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी को भिलाई नगर से पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशलूर जिला बस्तर, डीएसपी मनोज कुमार ध्रुव को नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रायपुर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला महासमुंद,

डीएसपी दिनेश कुमार सिंह को उप पुलिस अधीक्षक क्राइम जिला रायपुर से डीएसपी बीजापुर, डीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई, डीएसपी दीपक मिश्रा को रायगढ़ से डीएसपी गौरेला पेंड्रा मरवाही, डीएसपी आशीष कुमार बंछोर को नगर पुलिस अधीक्षक छावनी भिलाई से डीएसपी जिला बीजापुर, डीएसपी परवेज अहमद कुरेशी रायपुर से डीएसपी नारायणपुर, डीएसपी कल्पना वर्मा को नगर पुलिस अधीक्षक माना रायपुर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला दंतेवाड़ा भेजा गया है। सरकार ने 3 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी है। आईपीएस यशपाल सिंह को मोहला मानपुर जिले का नया एसपी बनाया? है। इसके साथ ही आईपीएस रत्ना सिंह को पीएचक्यू में एआईजी प्रशासन की जिम्मेदारी मिली? है। वहीं एटीएस के एसपी रहे अजातशत्रु बहादुर सिंह को एसडीआरएफ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ? आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 91 पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को एनआईए में अटैच कर दिया? है। अब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एनआईए भी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। अब एनआईए सिर्फ नक्सली हिंसा की जांच नहीं करेगी बल्कि नक्सलियों को गोला, बारूद, बम, बंदूक सहित अन्य संसाधन कहां से उपलब्ध होते हैं, इस बात का पता लगाएगी। लगातार एनआईए को मिल रहे केश को ध्यान में रखते हुए और उनकी सक्रियता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से डीजीपी ने 91 पुलिस? के अधिकारियों और कर्मचारियों को एनआईए में अटैच किया है।